एंटीबायोटिक उपयोग और प्रतिरोध में नाटकीय वृद्धि

दुनिया भर में एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर डिसीज़ डाएनामिक्स, इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिसी नामक संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मांग में सर्वाधिक वृद्धि निम्न व मध्यम आमदनी वाले देशों में देखी जा रही है। संस्था ने हाल ही में विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के अलावा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय निगरानी संस्थाओं की रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है।

सेंटर ने पिछले 10 वर्षों में 69 देशों में एंटीबायोटिक्स के उपयोग के रुझानों और 39 देशों में 12 किस्म के एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध की गणना की है।

रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 के बीच एंटीबायोटिक का वैश्विक उपयोग 30 प्रतिशत बढ़ा। इसमें से अधिकांश वृद्धि दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे देशों में देखी गई। इन देशों में दुकान से एंटीबायोटिक दवाइयां खरीदना बहुत आसान है।

उदाहरण के लिए भारत में *क्लेबसिएला न्यूमोनिए* के प्रतिरोधी संक्रमणों की तादाद 2008 में 29 प्रतिशत थी और 2014 में बढ़कर 57 प्रतिशत हो चुकी थी। ये उन संक्रमणों का प्रतिशत है जो शक्तिशाली एंटीबायोटिक कार्बेपेनीम के प्रतिरोधी साबित हुए हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया भर में पशुओं पर एंटीबायोटिक्स का उपयोग तेज़ी से बढ़ा है। समस्या खास तौर से चीन में गंभीर रूप ले चुकी है जहां 2010 में पशुओं के लिए 15,000 टन एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया गया।

दूसरी ओर, उच्च आमदनी वाले देशों में एंटीबायोटिक्स के उपयोग के नियमन की कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यू.के. जैसे देशों में मेथिसिलिन के प्रतिरोधी *स्टेफिलोकॉकस ऑरियस* संक्रमणों की संख्या पिछले आठ वर्षों में तेज़ी से कम हुई है।

रिपोर्ट के बारे में कई चिकित्सा शोधकर्ताओं का मत है कि यह रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है और मांग करती है कि निगरानी के प्रयास सघन किए जाएं, खास कर विकासशील देशों में, जहां फिलहाल आंकड़ों का अभाव है।

रिपोर्ट में एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए 6 उपायों का सुझाव दिया गया है। इनमें से कुछ उपाय तो जाने-माने हैं। जैसे स्वच्छता तथा शौच व्यवस्था में सुधार करना। मगर कृषि और अस्पतालों में एंटीबायोटिक के उपयोग को सीमित करने जैसे कदम इतने आसान नहीं हैं। ये काफी विवादास्पद भी साबित हो सकते हैं। इस संदर्भ में एंटीबायोटिक उपयोग की निगरानी के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के विकास की बात भी सामने आ रही है। ***(स्रोत फीचर्स)***